(ग) और (घ) किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता के लिए अर्हताओं को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 8 में रखा गया है। इन नियमों में किसी एकल परिवार से उन सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध विहित नहीं है जो किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्य बन सकते हों।

राजस्थान स्टाक एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज नहीं है जिसे कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की व्यवस्थाओं के तहत सरकार के द्वारा मान्यताप्राप्त हो।

Claims made to General Insurance Corporation following the Ayodhya incidents

*187. SHRI VIREN J. SHAH :
SHRI PROMOD MAHAJAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the number and amount of claims received by the General Insurance Corporation during the recent riots following the post Ayodhya Riots in the country particularly in Bombay, Gujarat, Bhopal, Delhi and Kashmir Valley ?

(b) What is the extent of loss of Life and property, vehicles, shops and houses, etc. in each of the places mentioned above for which claims have been filed;

(c) What is amount of compensation paid so far and to be paid by the Insurance companies;

(d) what steps Government have taken so far for early payment of claims to the affected persons; and

(e) what are the details of instructions issued by Government for the early disposal of claims by the Insurance Companies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (e) On account of the recent riots following the Ayodhya incidents, 3904 claims have been reported to New India Assurance Company Ltd., United India Insurance Company Ltd.; Oriental Insurance Company Ltd. and National Insurance Company Ltd. from all over the country. These claims pertain to vehicles, loss of life and property, shops, houses, etc. The split-up between the various categories of claims is not available. These claims amounted to Rs. 79.56 crores. The majority of the claims pertain to Bombay and Gujarat where 1816 and 1196 claims were reported. Out of them, 524 and 184 claims are motor vehicle related claims in Bombay and Gujarat respectively. Out of claims amounting to Rs. 79.56 crores preferred by the claimants, claims amounting to Rs. 6.08 crores have already been settled. In order to expedite the settlement of claims, Insurance Companies have been requested to set up Special Task Forces and Coordination Committees. The process of settlement of claims is being closely monitored and supervised at the Ministry level. Comprehensive guidelines and detailed procedures have been evolved by the General Insurance Corporation of India to ensure the expeditious settlement of these claims.

प्रशासनिक व्यय में कटौती किया जाना

*188. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष सरकार ने प्रशासनिक व्यय में कटौती करने और अनेक प्रशासनिक पदों में कमी लाने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है तथा वास्तव में किस सीमा तक उस निर्णय का अनुपालन किया जा सका है और यदि इस संबंध में की गई कार्यवाही में कोई शिथिलता आई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना एक सतत प्रक्रिया है। व्यय में किफायत बरतने अथवा फिजूल खर्ची से बचने के लिए किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा किए

गए उपायों में, विभिन्न स्तरों पर पदों में कमी करना, प्रथम श्रेणी में हवाई यात्रा पर रोक, दौरे के समय होटल में कमरों के सैट में रहने पर रोक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हवाई यात्रा और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी कोच में यात्रा करने पर रोक, घरेलू तथा अंतर्देशीय दोनों तरह की यात्रा में समग्र कटौती पैट्रोल/डीजल की खपत/व्यय में कमी करन, समयोपरि भत्ते के व्यय को नियंत्रित करना, 10% टेलीफोन लाइनों को वापस करना सम्मेलनों/सेमिनारों/ कार्यशालाओं, मनो-रंजनों, (मध्याह्न और रात्रि भोजों सहित), वाहन खरीदना, सजावटी लाईटिंग पर रोक लगाना, बिजली की खपत के व्यय में कटौती करना शामिल हैं। मंत्रालय-वार ब्यौरा किसी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। अतः इन उपायों के वित्तीय प्रभावों को बता पाना कठिन है।

Impact of PTV-2 on Indian Viewers

*189. Shri PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the influence and reach of PTV-2 (Second Channel of Pakistan Television) on Indian viewers; and

(b) if so, what steps Government are taking to check this ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO) : (a) Yes, Sir.

(b) Doordarshan is constantly endeavouring to bring about a qualitative and quantitative improvement in its programme content and format.

बिहार में ग्राम-पंचायतों में दूरभाष कनैक्शन दिया जाना

*190. श्री गया सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अभी तक कितनी ग्राम-पंचायतों में दूरभाष कनैक्शन दिए गए हैं,

(ख) सरकार द्वारा बाकी पंचायतों को कब तक दूरभाष कनेक्शन दिए जाने का विचार है, और

(ग) बिहार में कितने जिला-केन्द्रों में अभी तक एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) 28-2-1993 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा वाले पंचायत ग्रामों की संख्या 5123 है।

(ख) सभी पंचायत गांवों में 31- 3-95 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

Loan from IMF

*191. SHRI N. E. BALARAM :

SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have received the loan under stand by arrangements from IMF during the year 1992;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the conditions fulfilled by Government to get this loan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) An amount of SDR 1656 million was approved by the Board of Governors of the IMF on October 31, 1991 under Standby Arrangement. We have already drawn SDR 1425 million upto February 18, 1993. An amount of SDR 231 million is remaining, which is scheduled to be drawn in May, 1993.

(c) The conditions of IMF borrowings are contained in FM's letter of Intent and Memorandum of Economic Policy dated 27th August, 1991 and 2nd June, 1992, both of which have been laid on the Table of the House.